



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10022020-216035
CG-DL-E-10022020-216035

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]
No. 36]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 7, 2020/माघ 18, 1941
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 7, 2020/MAGHA 18, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2020

मामला सं. ओआई-01/2020

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा यहां से निर्यातित “सेल्फ-अधेसिव पॉलीविनाइल क्लोराइड फिल्म” के आयातों के संबंध में पाटन रोधी मूल जांच की शुरुआत।

फा. सं. 6/1/2020 डीजीटीआर.— 1.मै. पायोनियर पॉलीलेदर्स लिमि. (जिसे यहां “आवेदक” भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे यहां “अधिनियम” भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटन रोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण एवं क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे यहां “नियमावली” भी कहा गया है) के अनुसरण में, घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां “प्राधिकारी” भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. (जिसे यहां “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “सेल्फ-अधेसिव पॉलीविनाइल क्लोराइड फिल्म” जिसे सेल्फ-अधेसिव विनाइल, “अधेसिव विनाइल”, “विनाइल”, “विनाइल फिल्म”, “सेल्फ अधेसिव पी वी सी फिल्म”, “कोल्ड लेमिनेशन फिल्म” अथवा “एसएवी” के रूप में भी जाना जाता है (जिसे यहां “संबद्ध वस्तु” या विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद या “पीयूसी” भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटन रोधी शुल्क की मूल जांच के लिए एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति हो रही है और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित, संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने के लिए अनुरोध किया है।

विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद “सेल्फ-अधेसिव पॉलीविनाइल क्लोराइड फिल्म” या “एसएवी” है।
4. एसएवी का प्रयोग मुख्य रूप से व्यापार या व्यक्तिगत प्रयोग हेतु आकर्षक दिखने वाले सूचना-पट्ट और लोगोज के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग विज्ञापन हेतु इनडोर और आउटडोर ग्राफिक्स के विनिर्माण, दीवारों, खिड़कियों और कार्यालय या घर के क्षेत्रों की सजावट के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग जीवंत डिजाइनों और इमेजेज का सृजन करने तथा आसानी से विशेष प्रकार की स्याही को अवशोषित करने के लिए डिजिटल प्रिंटिंग प्रेस में भी किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग फ्लोरिंग टाइल्स के सृजन में भी प्रयोग किया जाता है क्योंकि अधेसिव सेकेंडों के लगभग घुमावदार या समतल गैर-मोटी सतह पर चिपका जाता है।
5. विचाराधीन उत्पाद को “प्लास्टिक और उससे बनी वस्तुएं” (उपशीर्ष 39199090) नाम से सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय 39 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। पीयूसी को 39191000, 39199010, 39199020, 39199090, 39209919, 39209959, 39209999, 39219099, 39269099 के अंतर्गत भी आयातित किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से जांच के क्षेत्र पर बाधित नहीं है।

समान वस्तु

6. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तुएं, जो भारत में पाटित की जा रही हैं, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के सदृश हैं। इन दोनों में न तो पाटित वस्तुओं की तकनीकी विशेषताओं, गुणवत्ता, कार्यो या अंतिम प्रयोग के संबंध में और न ही घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और आवेदक द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से एक दूसरे के प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए एडी नियमावली के तहत इन्हें “समान वस्तु” माना जाना चाहिए। इसलिए भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तुओं के “समान वस्तु” माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग

7. यह आवेदन मै. पायोनियर पॉलीलेदर्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक होने का दावा किया है। आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की बहुत कम मात्रा में आयात किया है। हालांकि ये आयात मामूली हैं। आवेदक ने दावा किया है कि इसका संबंध संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक या भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से नहीं है। उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि यह आवेदन नियमावली के नियम 2(ख) और 5(3) में निहित प्रावधानों के संबंध में “घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से” किया गया है।

कथित पाटन का आधार

8. आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण करने का अनुरोध किया है। आवेदक ने यह भी उल्लेख किया है कि चीन के अलावा, जापान, कोरिया और ताइवान से संबद्ध वस्तुओं की बहुत अधिक मात्रा में आयात हुआ है और यह दावा किया है कि ताइवान के लिए आयात की कीमतें अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य के उद्देश्य से उपयुक्त हैं। सभी हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे जांच की शुरुआत की तिथि से 30 दिनों के भीतर इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणियां दें।
9. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चूंकि जापान, कोरिया तथा ताइवान के बीच आयात की कीमतें संबद्ध वस्तुओं के लिए बहुत अलग-अलग होती हैं जो आवश्यक रूप से एक वस्तु हैं और इसलिए जांच की शुरुआत किए जाने के उद्देश्य से प्राधिकारी ने विधिवत समायोजित उत्पादन की लागत के आधार पर और बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्चों को उचित लाभ के साथ जोड़ने के बाद संबद्ध देश के लिए सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

10. प्राधिकारी ने संबद्ध देश की निर्यात कीमतों का परिकलन डीजीसीआई एंड सी के सौदावार आंकड़ों के अनुसार किया है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय माल भाड़ा व्ययों, पत्तन व्ययों और वैट प्रतिदाय के लिए समायोजन किया गया है।
11. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना गत स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के संबंध में महत्वपूर्ण पाटन मार्जिन को दर्शाता है, जिसके अनुसार, यह इंगित होता है कि संबद्ध देश में निर्यातको द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुएं पाटित की जा रही हैं।

क्षति और कारणात्मक संबंध

12. आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में आकलन हेतु अपनाया गया है। आवेदक ने कुल रूप में और घरेलू उद्योग पर कीमत प्रभाव के संबंध में पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप होने वाली क्षति के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देश से पाटित आयातों के परिणाम स्वरूप, लाभों, नियोजित पूंजी पर आय और नकदी प्रवाह में गिरावट के संबंध में इसके निष्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। संबद्ध देश से पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हो रही क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है जो पाटन रोधी जांच को शुरूआत का औचित्य सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है।

पाटन रोधी जांच की शुरूआत

13. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत पुष्टि किए गए लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीयूसी के कथित पाटन के संबंध में और ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसरण में, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, प्राधिकारी, एतद द्वारा, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में किसी कथित पाटन की विद्यमानता, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटन रोधी शुल्क, जो यदि लगाया जाता तो घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होता, की राशि की सिफारिश करने के लिए एक जांच की शुरूआत करते हैं।

संबद्ध देश

14. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

जांच की अवधि पो ओ आई

15. वर्तमान जांच में जांच की अवधि (जिसे यहां "पो ओ आई" भी कहा गया है) 1 अक्तूबर, 2018 से 30 सितम्बर, 2019 (12 महीने) है। क्षति जांच अवधि में अप्रैल 2016- मार्च 2017, अप्रैल 2017- मार्च 2018, अप्रैल 2018- मार्च 2019 और पीओआई की अवधि शामिल होगी।

प्रक्रिया

16. वर्तमान जांच के लिए नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का अनुपालन किया जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

17. संबद्ध देशों में निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के माध्यम से उनकी सरकार, विचाराधीन उत्पाद से संबंधित भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र और तरीके में सभी संगत सूचना दायर कर सकें।
18. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र और तरीके में जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकते हैं। सूचना/अनुरोध निम्नलिखित को प्रस्तुत किए जाएं:

निर्दिष्ट प्राधिकारी

व्यापार उपचार महानिदेशालय

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5 संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001

19. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार से यह अनुरोध है कि वह अन्य पक्षकारों को उसका अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराये।

समय-सीमा

20. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित में दी जानी चाहिए ताकि वह नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी को पहुँच जाए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उपर्युक्त नियमावली की व्याख्या के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाए जाने संबंधी सूचना उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुई मानी जाएगी जिसको वह प्राधिकारी द्वारा भेजी गई थी अथवा निर्यातक देश के उपर्युक्त कूटनीतिक प्रतिनिधि को भेजी गई थी। यदि कोई सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है अथवा सूचना अपूर्ण प्राप्त होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं।
21. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपने हित (हितों की प्रकृति सहित) सूचित करें और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

22. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (परिशिष्ट/उससे संलग्न अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को, यदि उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा किया गया है तो उसे दो अलग-अलग सेटों में दायर करना अपेक्षित है:

- i. गोपनीय के रूप में चिन्हित एक सेट (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, सूची आदि), और
- ii. अगोपनीय के रूप में चिन्हित दूसरा सेट (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, सूची आदि)।

23. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अनुरोध प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में स्पष्ट रूप से चिन्हित होने चाहिए। इस प्रकार के चिन्हों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने हेतु स्वतंत्र होंगे। दोनों रूपांतरों की सॉफ्ट प्रतियां भी प्रत्येक के चार (4) सेटों की हार्ड प्रतियों के साथ प्रस्तुत की जानी अपेक्षित होंगी।
24. गोपनीय रूपांतर में वह सभी सूचना होगी जो प्रकृति से गोपनीय और/अथवा अन्य सूचना है जिसको सूचना देने वाला गोपनीय होने का दावा करता है। जिस सूचना को प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना के संबंध में अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, उस सूचना के संबंध में सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ सही कारण का विवरण प्रदान करें कि उस सूचना का प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता।
25. अगोपनीय रूपांतर को गोपनीय सूचना के साथ अधिमानतः उस सूचना के आधार पर सूचीबद्ध अथवा ब्लैंक आउट (यदि सूचीकरण व्यवहार्य नहीं है) तथा सारांश का प्रदर्श होना अपेक्षित है जिसके आधार पर गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश गोपनीय आधार पर दी गई सूचना के सार की उपयुक्त समझ देने के लिए पर्याप्त व्यौरे में होने चाहिए। तथापि, अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह दर्शा सकते हैं कि यह सूचना सारांश के लिए संवेदनशील नहीं है; सारांश क्यों संभव नहीं है, इसका एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप दिया जाना चाहिए।
26. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा रद्द कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं हैं अथवा यदि सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक करने का अनिच्छुक है अथवा सामान्य रूप में या सारांश रूप में उसे प्रकट करने के लिए प्राधिकृत नहीं करना चाहता तो वे उसकी अनदेखी कर सकते हैं।
27. किसी सार्थक अगोपनीय रूपांतर के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में अच्छे कारण के विवरण के बिना किया गया कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।
28. प्राधिकारी संतुष्ट होने पर तथा दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करने पर उस सूचना को प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसे प्रकट नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

29. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

30. यदि कोई हितवद्ध पक्षकार सूचना देने से इंकार करता है अथवा अन्यथा उपयुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी उनके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को जैसा भी वे उचित समझे सिफारिश कर सकते हैं।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2020

Case No. OI 01/2020

Initiation of Anti-Dumping Original Investigation concerning imports of “Self-Adhesive Polyvinyl Chloride Film” originating in or exported from China PR.

F. No. 6/1/2020-DGTR.—1. M/s Pioneer Polyleathers Limited (hereinafter also referred to as “Applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”) for Original Investigation of Anti-dumping Duty concerning imports of “Self-Adhesive Polyvinyl Chloride Film”, also known as “self-adhesive vinyl”, “adhesive vinyl”, “vinyl”, “vinyl film”, “self-adhesive PVC film”, “cold lamination film” or “SAV” (hereinafter also referred to as “subject goods” or specifically as “product under consideration” or “PUC”, originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the “subject country”).

2. The Applicant has alleged that material injury to the Domestic Industry is being caused due to dumped imports from the subject country and has requested for imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

Product under consideration

3. The product consideration is “Self-Adhesive Polyvinyl Chloride Film” or “SAV”.
4. SAV is mainly used for manufacturing eye-catching signs and logos for business or personal use. It is also used to manufacture indoor and outdoor graphics for advertising, to décor walls, windows and areas in office or home. It is also used in digital printing press to create vibrant designs and images and readily absorbs certain types of ink. The product under consideration is also applied in the creation of flooring tiles because the adhesive backing sticks to almost curved or flat non-coarse surface within seconds.
5. The product under consideration is classified under Chapter 39 of the Customs Tariff Act in the name of ‘Plastics and articles thereof’ (subheading 3919 90 90). The PUC has also been imported under 39191000, 39199010, 39199020, 39199090, 39209919, 39209959, 39209999, 39219099, 39269099. The Custom classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation.

Like Article

6. The Applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no known differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the Applicant. The two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as ‘like article’ under the Rules. Therefore, the subject goods produced by the Applicant in India are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject country.

Domestic Industry

7. The Application has been filed by M/s Pioneer Polyleathers Limited. The Applicant has claimed to be the sole producer of the product under consideration. The Applicant has imported small quantity of subject goods from the subject country, however, the imports are negligible. The Applicant has claimed that it is

not related to any exporter or producer of subject goods in the subject country or any importer of PUC in India. On the basis of information available, the Authority is satisfied that the Application has been made 'by or on behalf of the domestic industry' in terms of the provisions contained in Rule 2 (b) and Rule 5 (3) of the Rules.

Basis of Alleged Dumping

8. The Applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and has requested to determine normal value in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules. The Applicant has also stated that besides China there are significant import of subject goods from Japan, Korea & Taiwan and has claimed that import prices for Taiwan is appropriate for the purpose of Normal Value as per Para 7 of Annexure I. All the interested parties are advised to offer their comment on this issue within 30 days from the date of initiation of the investigation.
9. Authority notes that since import prices amongst Japan, Korea and Taiwan vary significantly for the subject goods which are essentially a commodity, the Authority has therefore, considered the Normal Value for the subject country on the basis of cost of production, duly adjusted, and after adding selling, general & administrative expenses with reasonable profit, for the purpose of initiation of investigation.
10. The Authority has computed the export price from subject country as per Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction wise data. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses, and VAT refund.
11. The normal value and export price have been compared at ex-factory level, which prima facie show significant dumping margin in respect of the subject goods from the subject country, thereby, indicating that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.

Injury and Causal Link

12. Information furnished by the Applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and price effect on the domestic industry. The Applicant has claimed that its performance has been adversely impacted in respect of decline in profits, return on capital employed, and cash flow, as a result of dumped imports from subject country. There is sufficient prima facie evidence of the injury being caused to the domestic industry by dumped imports from subject country to justify initiation of an antidumping investigation.

Initiation of Anti-Dumping Investigation

13. On the basis of the duly substantiated written application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the PUC originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Subject Country

14. The subject country in the present investigation is China PR.

Period of Investigation

15. The Period of Investigation (hereinafter also referred to as "POI") in the present investigation is 1st October 2018 to 31st September 2019 (12 months). The injury investigation period will cover the periods April 2016- March 2017, April 2017- March 2018, April 2018- March 2019 and the POI.

Procedure

16. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

Submission of information

17. The known exporters in the subject country and their government through their Embassy in India, importers and users in India known to be concerned with the PUC and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

18. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below. The information/ submission may be submitted to:

The Designated Authority
Directorate General of Trade Remedies
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Government of India
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street
New Delhi-110001

19. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time-Limit

20. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting Country. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
21. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

22. The parties making any submission (including Appendices/Annexes attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:
- i. One set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
 - ii. The other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).
23. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies in four (4) sets of each.
24. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
25. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarised depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarisation is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
26. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.

27. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
28. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

Inspection of Public File

29. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

30. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority